

मुख्यमंत्री ने गुरु पूर्णिमा पर महन्त रामदास का सत्कार किया

उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर में पंचामृत से अभिषेक किया व परिसर में वृक्षारोपण किया

डींग/भरतपुर/जयपुर, 10 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुवार को डींग के पूंछरी का लौटा में श्रीनाथ जी के मंदिर में पंचामृत से अभिषेक तथा सपत्नीक पूजा-अर्चना की।

मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में संत-महात्माओं का गुरु पूजन कर आशीर्वाद

- मुख्यमंत्री भजनलाल ने भरतपुर में बड़ा हनुमान मंदिर के पास जन सुनवाई की। उन्होंने अधिकारियों को अभिजनों की परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिये।**



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा-अर्चना की और संत-महात्माओं का गुरु पूजन कर आशीर्वाद लिया।

हनुमान मंदिर में महंत रामदास महाराज का सत्कार-सम्मान किया। उन्होंने महंत को सम्मान राशि, श्रीफल, शॉल, मिठाई एवं गुरु वंदन संदेश भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया और मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के साथ बैठकर प्रसादी ग्रहण

की।

मुख्यमंत्री ने बड़ा हनुमान मंदिर परिसर के समीप जनसुनवाई भी की, जिसमें उन्होंने आमजन की परिवेदनाओं को सुना तथा अधिकारियों को परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण के

निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेदूम, विधायक जगत सिंह, बहादुर सिंह कोली, डॉ. शैलेश सिंह, नैक्षम चौधरी सहित, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।

वडोदरा हादसे के बाद एक्शन में गुजरात सरकार

- चार इंजीनियर सर्वपेंड किए, अन्य पुलों का तत्काल निरीक्षण करने के आदेश दिए।**

के महेनजर राज्य के अन्य पुलों का तुरंत गहन निरीक्षण करने का आदेश दिया है।

ज्ञातव्य है कि बुधवार सुबह वडोदरा के पादरा कस्बे के पास गंभीरा गांव के पास आणंद और वडोदरा जिलों को जोड़ने वाले चार दशक पुराने पुल का एक हिस्सा ढह जाने से कई वाहन महिसागर नदी में गिर गए थे।

वडोदरा जिले के पुलिस अधीक्षक रोहन आनंद ने दिन में बताया, अब तक 17 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि तीन से चार लोग अभी भी लापता हैं। तलाशी और बचाव अभियान अभी भी जारी है।

- प.बंगाल सरकार ने पुलिस जांच की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश की, कोर्ट ने रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने का निर्देश दिया है।**

सेन और न्यायमूर्ति स्मिता दास डे की खंडपीठ ने पुलिस की केस डायरी को भी देखा और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे चार सप्ताह बाद जांच में हुई आगे की प्रगति की नई रिपोर्ट पेश करें। मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। इस मामले में अदालत ने कहा कि पीड़िता के परिवार के वकील को रिपोर्ट की एक प्रति दी जा सकती है।

10 लाख भारतीय श्रमिकों की भर्ती की रिपोर्ट गलत ठहराई रूस ने

मास्को, 10 जुलाई। रूस के श्रम मंत्रालय ने आज उन रिपोर्टों को खिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि वह 2025 के अंत तक भारत से 10 लाख श्रमिकों की भर्ती करने की योजना बना रहा है। मांस्को टाइम्स ने यूराल चैबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रमुख अंद्रिई बेसेदिन के हवाले से कहा था कि भारतीय कामगारों के आने से देश में श्रमिकों

- रूस के श्रम मंत्रालय ने कहा कि भारत से मजदूरों की भर्ती का कोटा होता है जो नियोक्ता व क्षेत्र की जरूरत के आधार पर तय होता है।**

की कमी दूर होगी। इस बीच रूस के उद्योगपतियों और उद्यमियों के संघ ने भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कूल बनाने का विचार पेश किया है ताकि विशेष रूप से रूसी रोजगार बाजार के लिए कामगारों को तैयार किया जा सके। श्रम मंत्रालय ने बाद में आरबीसी समाचार वेबसाइट को बताया कि भारत से कामगारों की भर्ती कोटा द्वारा नियंत्रित होती है जो क्षेत्रों और नियोक्ताओं की ज़रूरतों के आधार पर एक साल पहले निर्धारित किया जाता है।

गुरु पूर्णिमा पर दो छात्रों ने गुरु की हत्या की

हरियाणा के हिसार जिले के एक गांव में प्रधानाचार्य की चाकू मार कर हत्या की

- पुलिस को स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिली है। इसमें दोनों आरोपी छात्र वारदात के बाद भागते नजर आ रहे हैं। आरोपी छात्रों की पहचान कर ली गई है। अभी दोनों फरार हैं।**

हिसार, 10 जुलाई। गुरु पूर्णिमा पर्व पर गुरुवार को हरियाणा के हिसार के बास बादशाहपुर गांव में स्थित करतार मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गुरुवार को एक सनसनीखेज वारदात के तहत स्कूल के प्रधानाचार्य जगबीर सिंह की दो छात्रों ने चाकू मारकर हत्या कर दी।

इस घटना ने स्कूल परिसर में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। वारदात के बाद दोनों छात्र वहां से फरार हो गये जिस वक्त यह वारदात हुई, उस समय स्कूल में पेपर चल रहा था। घायल प्रधानाचार्य को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाये। पुलिस को वारदात में शामिल चाकू मौके पर ही पड़ा मिला है। स्कूल स्टाफ ने बताया, यह बिल्डिंग नारनौद के पूर्व विधायक सरोज मोर के परिवार की है। इस बिल्डिंग को जगबीर सिंह ने दो साल

पहले लीज पर लिया था। अचानक हुए हमले से जगबीर सिंह ने बचने की कोशिश भी की, लेकिन छात्रों ने उन पर चाकूओं से वार करना जारी रखा। कुछ ही सेकेंड में शरीर पर कई वार किये। इससे जगबीर लहलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद दोनों आरोपी छात्र चाकू लहराते हुए वहां से भाग गये। वहां मौजूद टीचर और अन्य स्टाफ ने तुरंत घायल जगबीर को एक निजी अस्पताल में पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान कुछ देर बाद ही उनकी मौत हो गयी।

उधर, घटना के बाद स्कूल की भी छुट्टी कर दी गयी। पेपर दे रहे बच्चों को घर भेज दिया गया। सूचना मिलते ही थाना बास पुलिस अस्पताल पहुंची और मृतक जगबीर के

शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। एक टीम स्कूल भी भेजी गयी, जिसमें घटना के बारे में स्कूल स्टाफ और छात्रों से जानकारी ली। ‘सीन ऑफ क्राइम’ टीम ने भी मौके पर पहुंच कर साक्ष्य जुटाये।

थाना बास प्रभारी मनदीप सिंह ने बताया कि स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सामने आयी है। इसमें दोनों आरोपी छात्र वारदात के बाद भागते हुये नजर आ रहे हैं। आरोपी छात्रों की पहचान कर ली है। उन्हें पकड़ने के लिए टीमें लगायी गयी है। हमले का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा किया है।

पुलिस ने अभी तक जो जांच की है, उसमें सामने आया है कि प्रिंसिपल

‘आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
दस्तावेजों को स्वीकार करने पर चुनाव आयोग को विचार करना है। द्विवेदी ने कहा कि यह आयोग के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

मामले की सुनवाई 28 जुलाई को होगी जिसमें तीन मुख्य सवालों पर

नाबालिग का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता की मां ने 01 जुलाई, 2022 को गोविंदगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि अभियुक्त उसकी बेटी को शादी का झांसा देकर एक साल तक दुष्कर्म करता रहा। जब अभियुक्त के घरवालों को बताया तो उनके साथ मारपीट की गई। वहीं, बाद में डरा-धमकाकर राजीनामा करवा लिया। इसके बाद 27 जून को अभियुक्त उसकी बेटी को भगाकर ले गया। घटना के 3 दिन बाद पुलिस ने पीड़िता को गोटन रेलवे स्टेशन से बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। सुनवाई के दौरान, पीड़िता ने अदालत को बताया कि घटना के दिन अभियुक्त उसे डरा धमकाकर अपने साथ ले गया। रेलवे स्टेशन के पास उसे जूस पिलाया और वह बेहोश हो गई। इसके बाद उसे दूसरे दिन गोटन गांव में होश आया। यहां अभियुक्त ने दो दिन तक उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। वहीं बाद में रेलवे स्टेशन पर पुलिस आकर उसे ले गई। दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि पीड़िता की माता और उसके पिता के बीच पैसों के लेन-देन का विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

फोकस होता। क्या चुनाव आयोग के पास मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया को शुरू करने की शक्ति है? प्रक्रिया और तरीका क्या वैधानिक रूप से उचित है? क्या इतनी कम समयवाधि, जबकि नवंबर में बिकर चुनाव है, में इसे पूरा करना संभव है?

न्यायालय ने कहा कि मामला सुनवाई योग्य है। आयोग को 21 जुलाई तक जवाब दाखिल करना है और प्रत्युत्तर 28 जुलाई से सहेले।

न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा कि पुनरीक्षण प्रक्रिया चल सकती है, लेकिन कानून आधार को मान्यता देना है। और चुनाव आयोग इसे चुनौती नहीं दे सकता क्योंकि आधार का प्रबंधन गृह मंत्रालय के अधीन है, जैसा कि वरिष्ठ अधिकवक्ता कपिल सिब्बल ने बताया।

द्विवेदी ने सुझाव दिया कि मामला 2 अगस्त को सुना जाए, तब तक डाफ्ट सूची सामने आ जाएगी। और अगर एक करोड़ लोग छूट जाते हैं, तब कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है।

अभिषेक मनु सिंघवी ने आपति तिरुवनंतपुरम, 10 जुलाई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े हुए हैं। इस बार उन्होंने कांग्रेस को आपातकाल को लेकर घेरा है। उन्होंने कहा कि आपातकाल मेंअनुशासन और व्यवस्था के नाम पर क्रूरताकी गई।आपातकाल को भारत के इतिहास का महज काला अध्याय नहीं मानना चाहिए, बल्कि इसके सबक को पूरी तरह से समझना जरूरी है। उन्होंने आपातकाल में इंदिरा गांधी और संजय गांधी के कामों को लेकर सवाल उठाए।

एक मलयालम अखबार में प्रकाशित लेख में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने 25 जून 1975 और 21 मार्च 1977 के बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल के काले युग को याद किया। उन्होंने कहा कि अनुशासन और व्यवस्था के लिए किए गए प्रयास क्रूरता में बदल दिए गए। जिन्हें उचित नहीं ठहराया जा सकता। कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य शशि थरूर ने कहा कि इंदिरा गांधी के

जताते हुए कहा कि यदि प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी गई तो इसे अदालत में “अपरिवर्तनीय” के रूप में पेश किया जाएगा।

न्यायमूर्ति बागची और धूलिया ने कहा कि पूरी प्रक्रिया व्यक्ति की पहचान पर केंद्रित है। आप जानना चाहते हैं कि यह व्यक्ति ए है या बी। आधार इस पहचान के लिए है फिर भी आप आधार को मानने से इनकार कर रहे हैं।

चुनाव आयोग के वकील द्विवेदी ने कहा कि आधार सामान्य रूप से रहने वाले गैर-नागरिकों को भी जारी होता है और यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इस पर द्विवेदी को बताया गया कि चुनाव आयोग की सूची में से कम से कम पांच दस्तावेज ऐसे हैं जो जन्मतिथि या जन्म स्थान नहीं दर्शाते - जबकि जन्मतिथि व जन्म स्थान मतदाता सूची में शामिल होने की पात्रता को अनिवार्य

शर्तें हैं। सिंघवी ने कहा कि आधार एक वैधानिक पहचान पत्र है, जिसे सरकार स्वयं बढ़ावा देती रही है, लेकिन अब उसे अस्वीकार किया जा रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लाल बाबू हुसैन बनाम निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (1995) के फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि एक बार व्यक्ति मतदाता सूची में आ जाता है, तो इसका अर्थ है कि उसने अपनी नागरिकता के संदर्भ में अधिकारियों को संतुष्ट कर दिया है।

सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग के पास नागरिकता पर फैसला लेने का अधिकार नहीं है।

अधिवक्ता कपिस सिब्बल ने बताया कि राज्य सरकार के सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की केवल 14.1 प्रतिशत आबादी के पास मैट्रिक सर्टिफिकेट है और मात्र 2 प्रतिशत के पास पासपोर्ट है, लेकिन 87 प्रतिशत के पास आधार कार्ड है।

कांग्रेस सांसद थरूर ने कहा, आपातकाल भारत के इतिहास का काला अध्याय है इससे सबक लेना चाहिए

थरूर ने 25 जून 1975 और 21 मार्च 1977 के बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल के काले युग को याद किया। उन्होंने कहा कि अनुशासन और व्यवस्था के लिए किए गए प्रयास क्रूरता में बदल दिए गए। जिन्हें उचित नहीं ठहराया जा सकता।

कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य शशि थरूर ने कहा कि इंदिरा गांधी के

- शशि थरूर ने मलयालम अखबार में छपे लेख में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी और संजय गांधी की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए।**

पुत्र संजय गांधी ने जबरन नसबंदी अभियान चलाया। यह आपातकाल का गलत उदाहरण बना। ग्रामीण इलाकों में मनमाने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए

हिसा और जबरदस्ती की गई। नई दिल्ली जैसे शहरों में झुगियों को बेरहमी से ध्वस्त कर दिया गया और उन्हें साफ कर दिया गया। हजारों लोग बेघर हो गए।

‘गुजरात में सड़क, पुल, बांध टूटना आम हो गया, जांच के नाम पर लीपापोती हो रही है’

कांग्रेस ने वडोदरा पुल हादसे को लेकर गुजरात की भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना की

नयी दिल्ली, 10 जुलाई। कांग्रेस ने गुजरात में पुल ढ़ हने से कई लोगों के मारे जाने की घटना को अत्यंत चिंताजनक बताते हुए कहा है कि राज्य में चरम भ्रष्टाचार के बीच वहां ‘चंदा दो-धंधा लो’ की व्यवस्था चल रही है और अधिकारी लापरवाह हो गये हैं इसलिए रोड, पुल, कैनाल, डैम टूटना, अग्निकांड की घटनाएं लगातार हो रही हैं और इनकी जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती की जा रही है।

गुजरात कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी एवं सेवादल के अध्यक्ष लालजी देसाई ने गुरुवार को यहां कांग्रेस के नये मुख्यालय इंदिरा भवन में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं के लिए सरकार तुरंत जांच शुरू करवा देती है, लेकिन परिणाम शून्य रहता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार इस तरह के पिछले 16 मामलों में जांच के लिए ईमानदार अधिकारियों की टीम गठित नहीं करती है तो सड़कों पर उतरकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल तथा गृहमंत्री हर्ष रमेश संघवी के इस्तीफे की मांग की जाएगी।

- कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी, सेवा दल अध्यक्ष लालजी देसाई ने कहा, पिछले 16 मामलों में जांच टीम गठित हुई पर नतीजा शून्य रहा।**

- कांग्रेस नेताओं ने कहा, गुजरात सरकार ने तय कर लिया है दुर्घटना का हिस्सा बनिए, चार लाख रु. का मुआवजा लीजिए। यहां जान की कीमत मात्र 4 लाख रु. है।**

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब तक मीडिया और विपक्ष के तौर पर कांग्रेस का दबाव रहता है, तब तक कुछ लोगों की गिरफ्तारी कर लीपा-पोती की जाती है और छोटी मछलियों को पकड़ा जाता है, लेकिन भाजपा से जुड़े बड़े मगरमच्छों को छोड़ दिया जाता है। गुजरात सरकार और उनके भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत के कारण प्रदेश भर में पिछले कुछ साल में कई दुर्घटनाएं हुई हैं।

कांग्रेस नेताओं ने गुजरात में हाल में हुई दुर्घटनाओं का विवरण देते हुए कहा कि करीब तीन साल पहले मोरबी में सरकार की लापरवाही से 135 लोगों

की जान चली गई। राजकोट में जनता ने चेताया था, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया आखिर में गेमिंग जेन में आग लगने से कई लोगों की जान चली गई। वडोदरा में नाव पलटने से बच्चों समेत 14 लोगों की मौत हो गई थी। कुछ महीने पहले डीसा की एक फैक्ट्री में आग लगने से करीब 22 लोगों की मौत हो गई थी।

गुजरात सरकार ने मानो तय कर लिया है कि दुर्घटना का हिस्सा बनिए, जान दीजिए और चार लाख रुपए का मुआवजा ले जाइए- यानी यहां आम जनता की जान की कीमत मात्र चार लाख रुपए है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RA.JHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स: 0141-2373513, कोटा कार्यालय: पलायवा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय: कुम्भारा हाऊस, हनुमान हवा, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आचड़ मैन रोड आचड़, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स: 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चूंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालौर।फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डीनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डीनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरु कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरु, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908

● ● ● ● ●

⊕

● ● ● ● ●

⊕

● ● ● ● ●

⊕

● ● ● ● ●

⊕